समक्ष पी.पी.जैन, ए.सी.जे *और* डी.एस तेवतिया &

आई.एस तीवाना, माननीय न्यायमूर्ति।

बुध राम (मृतक), – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य – प्रतिवादी

क्रिमिनल रिवीजन नंबर . 798 का 1980

30 मार्च 1984

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (*1954* का *37)* - धारा *2(i-a), (1)* और (*m), 2(xii-a), 2(xiii), 7, 10, 16(1)* और *16* –ए–दूध–क्या प्राथमिक भोजन है–खाद्य निरीक्षक द्वारा चाय विक्रेता से चाय की पत्ती, चीनी या दूध के नमूने की खरीद–ऐसी वस्तुएं बिक्री के लिए नहीं बल्कि चाय की तैयारी में उपयोग के लिए संग्रहित की जाती हैं–ऐसी खरीद– क्या अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत विक्रेता द्वारा बिक्री के बराबर है - सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट जिसमें केवल खाद्य पदार्थ के विभिन्न घटकों के माप के बारे में डेटा और विश्लेषक की राय भी शामिल है ऐसी रिपोर्ट - क्या यह

की आवश्यकताओं को पूरा करती है अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत रिपोर्ट - धारा *16(1)* के तहत अपराधों का परीक्षण एक सारांश परीक्षण की आवश्यकता - चाहे अनिवार्य हो।

अभिनिर्णित, जब कृषि के व्यापक आयाम पर विचार किया जाता है तो यह माना जाता है कि इसमें बागवानी, वानिकी, डेयरी खेती आदि शामिल हैं। यह माना जाना चाहिए कि विधायिका को पता था कि अभिव्यक्ति 'कृषि' का संकीर्ण और व्यापक अर्थ है। यदि विधायिका का इरादा 'कृषि' शब्द का व्यापक अर्थ में उपयोग करने का था तो 'बागवानी' शब्द का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था क्योंकि कृषि के व्यापक अर्थ में बागवानी भी शामिल थी। इसलिए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि विधानमंडल द्वारा 'कृषि उपज' शब्द का उपयोग बागवानी की उपज के विपरीत मानव उपभोग के लिए भूमि पर खेती की जाने वाली वनस्पति साम्राज्य की प्राकृतिक उपज के संदर्भ में एक संकीर्ण अर्थ में किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भूमि पर पाले गए या भूमि की उपज पर पले जाने वाले पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम के कीड़ों को 'कृषि उपज' का हिस्सा बनाने का सवाल ही नहीं उठता। उपरोक्त से प्राप्त आगे की उपज के संबंध में ऐसा मामला अधिक स्पष्ट रूप से होगा। इसलिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

1954 की धारा 2(*xii-a)* के अर्थ के अंतर्गत दूध प्राथमिक भोजन नहीं है।

*(*पैरा *31 & 59)*

अभिनिर्णित, विश्लेषण के प्रयोजन के लिए खाद्य निरीक्षक को मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बिक्री माना जाता है और यदि विश्लेषण पर बेचा गया खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया जाता है तो अपराध पूरा हो जाता है और यह की ओर से आवश्यक नहीं है. अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होगा कि खाद्य निरीक्षक को बेची गई खाद्य सामग्री विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए भेजी गई थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार खाद्य निरीक्षक द्वारा चाय विक्रेता द्वारा रखे गए दूध या चीनी या चाय के नमूने की खरीद बिक्री के लिए नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को परोसने के लिए चाय तैयार करने में उपयोग करने के लिए की जाती है। अधिनियम की धारा 2(xiii) के साथ पठित धारा 7 के संदर्भ में बिक्री के बराबर है।

(पैरा 32 और 59)

अभिनिर्णित, कि एक रिपोर्ट जिसमें विभिन्न घटकों का माप दिया गया है और फिर उल्लेख किया गया है कि ऐसे घटक निर्धारित मानक से नीचे हैं या कानून द्वारा निर्धारित अनुपात में मौजूद नहीं हैं और आगे विश्लेषक

की राय का उल्लेख है कि विश्लेषण किया गया नमूना मिलावटी था, इसे रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है अपर्याप्त डेटा युक्त. ऐसी रिपोर्ट में न केवल वे निष्कर्ष शामिल होते हैं जिनसे यह राय बनती है कि नमूना मिलावटी है बल्कि वह डेटा भी शामिल होता है जिस पर ऐसा निष्कर्ष आधारित होता है। इस प्रकार, सार्वजनिक विश्लेषक की एक रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्ट के रूप में कानून में स्वीकार्य माना जाता है, जिसमें नमूना मिलावटी था या नहीं, यह तय करने के लिए सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षणों के तरीके और तरीके के बारे में जानकारी शामिल नहीं होती है। यदि वह रिपोर्ट में अपने द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों को इंगित करता है तो यह पर्याप्त है।

(पैरा 51 और 59)

अभिनिर्णित, विधानमंडल का इरादा है कि अधिनियम की धारा 16(1) के तहत सभी अपराधों की सुनवाई विशेष रूप से अधिकृत मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाए, जब तक कि ऐसा मजिस्ट्रेट लिखित रूप में यह राय न दे कि अभियुक्त अधिक सजा का हकदार है और इसलिए उस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाया जाए। दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा. लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त सुनवाई तभी कर सकते हैं जब वे विशेष रूप से इतने सशक्त हों। इसलिए, जब तक कि वे विशेष रूप से इतने सशक्त न हों, उनके सारांश परीक्षण आयोजित करने का प्रश्न ही

नहीं उठता। हालाँकि, एक बार जब न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष रूप से इतने सशक्त हो जाते हैं, तो वे एक मामले और दूसरे मामले के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं और उन्हें धारा 16(1) के तहत हर अपराध की सुनवाई पहली बार में सारांशित तरीके से करनी होगी और यदि कोई अपराध ऐसा है कि अपराधी को सारांश परीक्षण के परिणामस्वरूप दी जा सकने वाली सजा से अधिक सजा दिए जाने की आवश्यकता है, तो उस मामले में लिखित रूप में ऐसा आदेश पारित करने के बाद, वह ऐसे अपराधियों पर संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाने का हकदार हो सकता है। दिया गया अपराध: इसलिए, अधिनियम की धारा 16(1) के तहत अपराधों का सारांश परीक्षण आयोजित करना तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त नहीं किया जाता है। एक बार जब वे इतने सशक्त हो जाते हैं, तो धारा 16(1) के तहत प्रत्येक मामले को पहली बार में अनिवार्य रूप से सारांशित तरीके से आजमाया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट उक्त प्रावधान में उल्लिखित कारणों से प्रक्रिया के अनुसार अपराधी पर मुकदमा चलाना आवश्यक न समझे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित।

(पैरा 58 & 59)

गोपी चंद, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*।

आई.एस बल्हारा, एडवोकेट, प्रतिवादी *के लिए*।

निर्णय

डी.एस तेवतिया, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) 1980 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 798 पहली बार सुनवाई के लिए पुंछी, जे. के समक्ष आया, जिन्होंने 8 अक्टूबर, 1982 के अपने आदेश द्वारा इसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इसके बाद मामला एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसके अलावा पुंछी, जे. मैं एक पार्टी थी। हमने 2 फरवरी, 1984 के अपने आदेश द्वारा मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया।

(2) 1983 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 791, जिसे स्वीकार करने वाली पीठ ने 1980 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 798 के साथ सुनने का आदेश दिया था, को उसी के साथ डिवीजन के समक्ष रखा गया और बाद की पुनरीक्षण याचिका में संदर्भ आदेश के मद्देनजर पूर्व इसे भी बड़ी बेंच के पास भेजा गया।

(3) 1982 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1347 को बैंस, जे. द्वारा बड़ी पीठ को भेजा गया था और प्रेम चंद जैन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और आईएस तिवाना, जे. की खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1984 के तहत इसे संदर्भित किया था। यह और भी बड़ी बेंच के पास है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों आपराधिक पुनरीक्षण केवल कुछ कानूनी

प्रश्नों के निर्णय हेतु हमारे समक्ष रखे गये हैं। चूँकि कानून के वे प्रश्न जिन पर निर्णय की आवश्यकता है, तीनों पुनरीक्षण याचिकाओं में समान हैं, इसलिए एक सामान्य निर्णय प्रस्तावित है।

(4) उक्त तीन पुनरीक्षण याचिकाओं में इस बड़ी पीठ के विचार के लिए उठने वाले कानून के प्रश्न जब सटीक रूप से तैयार किए जाएंगे तो वे पढ़ेंगे: -

1. क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2(xiia) के अर्थ के अंतर्गत 'दूध' प्राथमिक भोजन है?

2. क्या अधिनियम की धारा 10 के अनुसार खाद्य निरीक्षक द्वारा दूध या चीनी या चाय विक्रेता द्वारा रखी गई चाय का नमूना बिक्री के लिए नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को परोसने के लिए चाय तैयार करने में उपयोग करने के लिए खरीदा गया है। अधिनियम की धारा 2(xiii) के साथ पठित धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार बिक्री के बराबर है?

3. क्या सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट जिसमें केवल दिए गए खाद्य पदार्थ के विभिन्न घटकों के माप के बारे में डेटा और यह राय शामिल है कि दिया गया नमूना मिलावटी था या नहीं, एक सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की कानूनी आवश्यकता को पूरा कर सकती है?

4. क्या अधिनियम की धारा 16(1) के तहत अपराधों के मुकदमे की पहली बार में सारांश तरीके से सुनवाई

की परिकल्पना करने वाला अधिनियम की धारा 16-ए का प्रावधान चरित्र में अनिवार्य है?

(5) उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 से 3 को तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखने के उद्देश्य से, हम 1980 के आपराधिक संशोधन संख्या 798 में प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है:

(6) खाद्य निरीक्षक, रेवाडी, श्री एस. जैसा कि अधिनियम के तहत परिकल्पित है, लिखित में नोटिस देते हुए, खाद्य निरीक्षक ने याचिकाकर्ता से 600 मि.ली. खरीदा। विश्लेषण के लिए दूध के बदले में रु. एक बाल्टी से 1.30 - जिसमें 4 लीटर गाय का दूध है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1974 (इसके बाद 'नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 में दिए गए फॉर्म III में सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 25 अक्टूबर, 1977 के अनुसार सार्वजनिक विश्लेषक को भेजे गए नमूने में दूध वसा 2.2 थी। प्रतिशत और दूध के ठोस पदार्थ वसा नहीं 7.1 प्रतिशत। दूध में वसा की कमी 45 प्रतिशत और दूध के ठोस पदार्थों में वसा की कमी न्यूनतम निर्धारित मानकों से 14 प्रतिशत कम होने की राय व्यक्त की गई। याचिकाकर्ता पर न्यायिक

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रेवाडी द्वारा मुकदमा चलाया गया, जिन्होंने उसे अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत अपराध का दोषी पाया और उसे छह महीने के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 1,000, डिफ़ॉल्ट रूप से तीन महीने का आरआई। वह सजा अधिनियम की धारा 16(1) (ए) (आई) के तहत लगाई जाने वाली न्यूनतम सजा थी। याचिकाकर्ता की अपील विफल हो गई जिसके कारण उसे इस न्यायालय में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर करनी पड़ी।तथ्यों के आलोक में, जैसा कि दलील दी गई है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमें यह देखना होगा कि क्या इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होगा।

(7) प्राथमिक भोजन की अवधारणा को 1 अप्रैल, 1976 से अधिनियम में पेश किया गया, 1976 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा, जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है (इसके बाद, संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है)।

(8) संशोधन अधिनियम ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 2 के खंड (आईए) में दो उप-खंड टी' और 'एम' जोड़े जो 'मिलावटी' अभिव्यक्ति को परिभाषित

करते हैं। नए जोड़े गए उप-खंड निम्नलिखित शर्तों में हैं: -

2(ia) "मिलावटी"-खाद्य वस्तु को मिलावटी माना जाएगा:-

(एल) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से नीचे आती है या उसके घटक परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं मात्रा में मौजूद हैं, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है

(एम) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से नीचे आती है या उसके घटक परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाते हैं:

बशर्ते, जहां वस्तु की शुद्धता की गुणवत्ता, प्राथमिक भोजन होने के नाते, निर्धारित मानकों से नीचे गिर गई हो या उसके घटक परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं मात्रा में मौजूद हों, किसी भी मामले में, केवल प्राकृतिक कारणों से और नियंत्रण से परे मानव एजेंसी की, तो ऐसे लेख को इस उप-खंड के अर्थ में मिलावटी नहीं माना जाएगा।

(9) उप-खंड (xii-a) जो अभिव्यक्ति 'प्राथमिक भोजन' को परिभाषित करता है, संशोधन अधिनियम द्वारा उप-खंड (xii) के बाद जोड़ा गया था और यह पढ़ता है: -

> "प्राथमिक भोजन' का अर्थ भोजन का कोई भी लेख है, जो अपने प्राकृतिक रूप में कृषि या बागवानी की उपज है।"

(10) अधिनियम में निषेधात्मक प्रावधान अधिनियम की धारा 7 है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंत में एक स्पष्टीकरण जोड़ने के साथ संशोधन भी किया गया है। इस प्रकार संशोधित होने के बाद धारा 7 इस प्रकार है: -

> 7. कुछ खाद्य वस्तुओं के निर्माण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध।
>
> कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिए निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा-
>
> (i) कोई भी मिलावटी भोजन;
>
> (ii) कोई भी गलत ब्रांड वाला भोजन;
>
> (iii) खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु जिसकी बिक्री के लिए लाइसेंस निर्धारित है, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार छोड़कर;

(iv) कोई भी खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा फिलहाल प्रतिबंधित है (सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में);

(v) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ;

(vi) कोई भी मिलावटी पदार्थ।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति किसी भी मिलावटी भोजन या गलत ब्रांड वाले भोजन या खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट किसी खाद्य पदार्थ का भंडारण करने वाला समझा जाएगा यदि वह ऐसा भोजन भंडारित करता है। बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ के किसी भी लेख के निर्माण के लिए।

(11) धारा 10 जो खाद्य निरीक्षक की शक्तियों की गणना करती है, उसे भी धारा 10 की उपधारा (2) के एक प्रावधान द्वारा संशोधित किया गया है, उसे प्राथमिक भोजन के रूप में किसी भी खाद्य पदार्थ का नमूना लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यदि उसका इरादा नहीं था। ऐसे भोजन के रूप में बिक्री. धारा 10 की उपधारा (1)

और उपधारा (2) जो संशोधन के बाद विवाद के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार पढ़ें: -

> खाद्य निरीक्षकों की शक्तियाँ.-(1) एक खाद्य निरीक्षक के पास शक्ति होगी- क) किसी भी खाद्य पदार्थ के नमूने लेने के लिए-
>
> (i) ऐसी वस्तु बेचने वाला कोई भी व्यक्ति;
>
> (ii) कोई भी व्यक्ति जो किसी क्रेता या परेषिती को ऐसी वस्तु पहुंचाने, वितरित करने या वितरित करने की तैयारी कर रहा हो;
>
> (iii) किसी परेषिती को ऐसी किसी वस्तु की डिलीवरी के बाद; और
>
> (बी) ऐसे नमूने को उस स्थानीय क्षेत्र के सार्वजनिक विश्लेषक के पास विश्लेषण के लिए भेजना, जिसके भीतर ऐसा नमूना लिया गया है;
>
> (सी) संबंधित स्थानीय क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के साथ, या सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य पदार्थ की किसी भी वस्तु की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की पिछली मंजूरी के साथ।

स्पष्टीकरण.- खंड (ए) के उप-खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए, "कंसाइनी" में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपने उपभोग के लिए भोजन का कोई लेख खरीदता है या प्राप्त करता है।

(2) कोई भी खाद्य निरीक्षक किसी ऐसे स्थान में प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है जहां किसी खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है या बिक्री के लिए भंडारण किया जाता है, या बिक्री के लिए किसी अन्य खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए भंडारण किया जाता है, या sdle के लिए उजागर या प्रदर्शित किया जाता है या जहां किसी भी मिलावट का निर्माण किया जाता है या रखे, और विश्लेषण के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ या मिलावट के नमूने लें:

बशर्ते कि किसी भी खाद्य पदार्थ का, जो प्राथमिक भोजन है, कोई नमूना इस उपधारा के तहत नहीं लिया जाएगा, यदि वह ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में बिक्री के लिए अभिप्रेत नहीं है।

धारा 16 जो दंड भी निर्धारित करती है, उसे अन्य बातों के साथ-साथ, उप-धारा (1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर, संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है -

"उसे उपलब्ध कराया-

(i) यदि अपराध खंड (ए) के उप-खंड (i) के तहत है और खाद्य पदार्थ के एक लेख के संबंध में है, प्राथमिक भोजन है, जो मानव एजेंसी के कारण मिलावटी है या भोजन के एक लेख के संबंध में है जो धारा 2 के खंड (ix) के उप-खंड (k) के अर्थ में गलत ब्रांड किया गया है; या

(ii) यदि अपराध खंड (ए) के उप-खंड (ii) के तहत है, लेकिन उप-धारा (1-ए) के खंड (ए) या खंड (जी) के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के संबंध में अपराध नहीं है। धारा 23 या धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (बी) के तहत।

अदालत, फैसले में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, कारावास की सजा दे सकती है जो तीन महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो पांच से कम नहीं होगा सौ रुपये:

बशर्ते कि यदि अपराध खंड (ए) के उपखंड (ii) के तहत है और धारा 23 की उपधारा (1-ए) के खंड (जी) के खंड (ए) के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के संबंध में है। या धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (बी) के तहत, अदालत फैसले में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए कारावास की सजा दे सकती है जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो पाँच सौ रुपये तक बढ़ायी जा सकती है।

(12) याचिकाकर्ता के मामले में इस निष्कर्ष की प्रासंगिकता कि दूध 'प्राथमिक/आहार' है, धारा 16 में जोड़े गए परंतुक पर नज़र डालने से और सामान्य रूप से 'मिलावट' की परिभाषा में किए गए संशोधन पर नज़र डालने से स्पष्ट हो जाती है। और अधिनियम की धारा 7 और धारा 10 में संशोधन किया गया।

(13) उच्च न्यायालयों ने इस प्रश्न का एक समान उत्तर नहीं दिया है कि क्या 'दूध' 'प्राथमिक भोजन' है जैसा कि वर्तमान में दिखाया जाएगा। समय की दृष्टि से केरल उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सबसे पहले आता है। पोटी, जे., जैसा कि वह उस समय केरल राज्य बनाम अब्दुल

कादर (1) में थे, ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की है कि दूध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 2 (xiia) के संदर्भ में प्राथमिक भोजन है। नटवरलाल सी. शाह फूड इंस्पेक्टर बनाम प्रभातभाई पंजाबी (2) मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी पोटी, जे. के उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया है।

(14) घर के नजदीक, इस न्यायालय ने लगातार केरल और गुजरात उच्च न्यायालयों के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। बिंदुवार निर्णय किशन लाई बनाम पंजाब राज्य (8), हरियाणा राज्य बनाम जगदीश (4) हैं। मेघ सिंह बनाम राज्य (5) और मुमताज खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने (5-ए) ने भी ऐसा ही रुख अपनाया है।

(15) सम्मान के साथ, हम खुद को उस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं जो अब्दुल कादर के मामले (सुप्रा) में केरल उच्च न्यायालय और नटवरलाल के मामले (सुप्रा) में गुजरात उच्च न्यायालय ने लिया है।

(16) पोती, जे. ने अपने विचार के समर्थन में मुख्य रूप से आईटी कॉमरेड में मद्रास उच्च न्यायालय के

फैसले के अनुपात को आधार बनाया है। बनाम सुंदरा मुदलियार (6) और आयकर आयुक्त बनाम बेनॉय कुमार (7) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गुजरात उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उनके दृष्टिकोण और बेनॉय कुमार के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य पर आधारित है।

(17) बेनॉय कुमार के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने भगवती, जे. के माध्यम से बोलते हुए, जिन्होंने बेंच के लिए राय दी थी, 'कृषि' शब्द की व्यापक अर्थ में व्याख्या करने के खिलाफ सलाह दी है जैसा कि वर्तमान में दिखाया जाएगा।

(18) बिनॉय कुमार के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या निर्धारिती के स्वामित्व वाले जंगल में साल और पियासल के पेड़ों से प्राप्त आय, जो मूल रूप से सहज विकास का जंगल था, मानव कौशल की सहायता से नहीं उगाया गया था और श्रम, लेकिन जिस पर मामले के बयान में वर्णित 'वानिकी संचालन' निर्धारिती द्वारा किया गया था, जिसमें मानव कौशल और श्रम की काफी मात्रा में व्यय शामिल था, धारा 2 (i) के अर्थ के तहत कृषि आय है और इस तरह छूट दी गई है भारतीय आयकर

अधिनियम की धारा 4(3)(viii) के तहत कर के भुगतान से।

(19) अधिनियम की धारा 2(1) कृषि आय को परिभाषित करती है और उसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"(1) 'कृषि आय' का अर्थ है

(ए) भूमि से प्राप्त कोई भी किराया या राजस्व, जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और या तो कर योग्य क्षेत्रों में भू-राजस्व के लिए मूल्यांकन किया जाता है या सरकार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और संग्रहित स्थानीय दर के अधीन होता है:

(बी) ऐसी भूमि से प्राप्त कोई भी आय-

(i) कृषि, या

(ii) किसी कृषक या लगान के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्रक्रिया का निष्पादन जो आमतौर पर उसके द्वारा उगाए गए या प्राप्त किए गए उत्पाद को बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए नियोजित किया जाता है, या

(iii) किसी कृषक या किराए के प्राप्तकर्ता द्वारा उसके द्वारा उगाई गई या प्राप्त की गई उपज की बिक्री, जिसके संबंध में उप-खंड (ii) में वर्णित प्रकृति की प्रक्रिया के अलावा कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। ....

(20) चूंकि अधिनियम में 'कृषि' या 'कृषि उद्देश्य' शब्द की कोई परिभाषा नहीं थी, इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो गया कि उक्त शब्दों का क्या अर्थ है। उनके आधिपत्य ने महसूस किया कि चूंकि 'कृषि' और 'कृषि उद्देश्य' शब्दों को भारतीय आयकर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए आवश्यकता से बाहर किसी को सामान्य ज्ञान पर वापस आना होगा जिसमें उक्त अभिव्यक्ति को आम बोलचाल में समझा गया था . उनके आधिपत्य के अनुसार, अपने मूल अर्थ में 'कृषि' का अर्थ है कृषि, एक क्षेत्र और संस्कृति, खेती, खेत की खेती, जिसका अर्थ निश्चित रूप से भूमि पर मानव कौशल और श्रम का व्यय है। उनके आधिपत्य को पता था कि 'कृषि' और 'कृषि उद्देश्य' शब्दों ने एक व्यापक अर्थ प्राप्त कर लिया है जो कि विभिन्न शब्दकोश अर्थों में पाया जा सकता है। आर. वी. पीटर्स 7(ए) में लॉर्ड कोलरिज की निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा दृढ़ होने के बाद उनके आधिपत्य ने विभिन्न शब्दकोशों से 'कृषि' या 'कृषि उद्देश्य' अभिव्यक्ति का अर्थ उद्धृत किया:

"मैं इस बात से भली-भांति परिचित हूं कि शब्दकोशों को संसद के अधिनियमों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों के आधिकारिक प्रतिपादक के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए,

लेकिन न्यायालयों का यह एक प्रसिद्ध नियम है कि शब्दों को उनके सामान्य अर्थ में उपयोग किया जाना चाहिए" और इसलिए हमें इन पुस्तकों की शिक्षा के लिए भेजा गया है।

और कैमडेन (मार्क्विस) बनाम अंतर्देशीय राजस्व में कोजेंस-हार्बी, एम.आर
कमिश्नर, (7-बी):
“यह न्यायालय का काम है कि वह क़ानून की यथासंभव सर्वोत्तम व्याख्या करे। ऐसा करने में न्यायालय निस्संदेह अपने द्वारा पाए गए किसी भी साहित्यिक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में सहायता कर सकते हैं, जिसमें निश्चित रूप से मानक लेखकों का परामर्श और प्रसिद्ध और आधिकारिक शब्दकोशों का संदर्भ भी शामिल है।

(21) 'कृषि' शब्द के विभिन्न शब्दकोश अर्थों का उल्लेख करने के बाद उनके आधिपत्य ने 'कृषि' शब्द के सही अर्थ की खोज में अपना ध्यान विभिन्न निर्णयित मामलों की ओर लगाया।

(22) उनके आधिपत्य की जांच के दायरे में लाए गए निर्णयित मामलों के अनुपात और उन मामलों में संदर्भित 'कृषि' शब्द के शब्दकोष के अर्थ से, जो परिणामी स्थिति सामने आई वह यह थी कि 'कृषि' शब्द संकीर्ण अर्थ में है जब इसे भूमि पर किए गए कृषि कार्यों के संबंध में लागू किया जाता है, तो शब्द के सख्त अर्थ में भूमि की खेती

होती है, जिसका अर्थ है कि भूमि की जुताई, बीज बोना, रोपण और भूमि पर इसी तरह के संचालन जिन्हें उनके आधिपत्य ने वर्गीकृत किया है 'बुनियादी कार्य?.. कृषि कार्यों के संदर्भ में 'कृषि' शब्द का व्यापक अर्थ हालांकि जल्द ही ऐसे 'कृषि कार्यों' को शामिल करने लगा है जो भूमि से उपज उगने के बाद किए जाते हैं, उदाहरण के लिए, निराई करना, मिट्टी खोदना, हटाना अवांछनीय कम वृद्धि और अन्य सभी कार्य जो विकास को बढ़ावा देते हैं, न केवल कीड़ों और कीटों से बल्कि बाहर से होने वाली क्षति से भी बचाते हैं, देखभाल, छंटाई, कटाई, कटाई और उत्पाद को बाजार के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इन बाद के ऑपरेशनों को उनके आधिपत्य द्वारा 'बाद के ऑपरेशन' के रूप में वर्गीकृत किया गया। संकीर्ण अर्थ में उत्पादन के संबंध में 'कृषि' शब्द मनुष्यों और जानवरों के लिए भोजन उत्पादन तक ही सीमित था। व्यापक अर्थ में 'कृषि उपज' शब्द में न केवल अनाज और फलों की सब्जियाँ जैसे उत्पाद शामिल हैं जो मनुष्यों के भरण-पोषण के लिए आवश्यक हैं, बल्कि इसमें जानवरों के उपभोग के लिए वृक्षारोपण, उपवन या घास और चारागाह भी शामिल हैं। विलासिता जैसे पान, कॉफी, चाय, मसाले, तम्बाकू आदि या वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, सन, जूट, भांग, नील आदि।

(23) अपने व्यापक अर्थ में 'कृषि' शब्द में भूमि से संबंधित या भूमि से संबंध रखने वाली सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें पशुधन का प्रजनन और पालन, डेयरी

फार्मिंग, मक्खन और पनीर की खेती, मुर्गीपालन आदि शामिल हैं।

(24) निर्णय किए गए मामलों में से उनके आधिपत्य ने तब बताया कि 'कृषि' शब्द पर संकीर्ण निर्माण घश्याम अयंगर, जे. द्वारा मुरुगेसा चेट्टी बनाम चिन्नाथम्बी गौंडन (8) में अपनाया गया था और इसके व्यापक अर्थ की वकालत रीली जे. द्वारा की गई थी। चन्द्रशेखर भारती स्वामीगल वी. दुरईसामी नायडू (9) और विश्वनाथ शास्त्री द्वारा, कॉमरेड में जे. आयकर विभाग, मद्रास बनाम के.ई. सुंदरा मुदलियार (10)।

(25) उनके आधिपत्य ने उन निर्णयों पर भी ध्यान दिया, जिनमें 'कृषि' शब्द को भूमि के संबंध में सभी गतिविधियों को शामिल किया गया था, (सम्राट बनाम अलेक्जेंडर एलन (11)। उस मामले में सवाल यह उठा कि क्या भूमि का उपयोग केवल कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था अपने इस निष्कर्ष के लिए कि 'कृषि' शब्द में पशुधन के पालन-पोषण के लिए भूमि का उपयोग शामिल है, निर्भरता को मुर्रे के न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी गई कृषि शब्द की परिभाषा पर रखा गया था। विश्वनाथ शास्त्री, जे. ने भी 'कृषि' शब्द की व्यापक परिभाषा पर भरोसा किया ' मरे की न्यू ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी और वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार और निम्नानुसार आयोजित: -

“चारागाह भूमि का उपयोग किया गया! पशुधन को खिलाने और पालने के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि है: आईएलआर 25 मैड 627 पीपी 629, 630 (वी) पर। गाय, भैंस, भेड़ और मुर्गी जैसे पशुओं का पालन "पालन" में शामिल है। इन जानवरों को फसलों, जड़ों, फूलों और पेड़ों की तरह ही मिट्टी का उत्पाद माना जाता है, क्योंकि वे भूमि पर रहते हैं और उसी से अपना भरण-पोषण करते हैं। मिट्टी और उसकी उपज: 1938-6 आईटीआर 502 पृष्ठ पर। 509 (एआईआर 1938 रंग 260 पृष्ठ 261 पर) (एफबी) (एक्स); 1833 ए सी 618 (एचएल) 638 (जेड)। इसलिए मेरी राय में "कृषि" शब्द को गेहूं, चावल, रागी, कपास, तम्बाकू, जूट आदि जैसी वार्षिक या आवधिक फसलों वाले खुले मैदान की खेती तक सीमित रखना वैध नहीं है। कैसुरीना आमतौर पर गरीबों की सूखी भूमि पर उगाई जाती है। गुणवत्ता और यह सामान्य बात है कि उसी भूमि का उपयोग वैकल्पिक रूप से सामान्य अनाज वाली फसलों जैसे मूंगफली, जिंजरिली, छोटाम, कम्बू, आदि की खेती और कैसुरीना वृक्षारोपण के लिए किया जाता है। उगाई गई फसल की प्रकृति कुछ भी हो, भूमि शुष्क मूल्यांकन सहन करती है।

(26) 'कृषि' शब्द के संकीर्ण या व्यापक अर्थ को स्वीकार करने के संबंध में सावधानी बरतते हुए उनके आधिपत्य ने कहा कि किसी विशेष मामले में 'कृषि' शब्द के संकीर्ण या व्यापक अर्थ को अपनाया जाना चाहिए या नहीं, यह न

केवल विभिन्न प्रावधानों पर निर्भर करता है। ऐसे क़ानून जिनमें ऐसा ही होता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी। एक क़ानून में शब्द की परिभाषा दूसरे क़ानून में उसी शब्द के निर्माण के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देती है और जिस अर्थ में शब्द को कई क़ानूनों में समझा गया था, वह आवश्यक रूप से उस शब्द के तरीके पर कोई प्रकाश नहीं डालता है इसे सामान्यतः समझा जाना चाहिए।

(27) उपरोक्त परीक्षण के आलोक में बेनॉय कुमार के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य ने माना कि किसी उपज को 'कृषि उपज' माना जाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि उपज को कृषि संचालन को नियोजित करके उठाया गया था क्योंकि इसे 'बाद के संचालन' में वर्गीकृत किया गया था। उनके आधिपत्य का मानना था कि जब तक भूमि पर उपज उगाने में "बुनियादी कार्रवाई" नहीं की जाती, तब तक उक्त उपज को कृषि उपज नहीं माना जा सकता। उनके आधिपत्य 'कृषि' शब्द के अर्थ के विस्तार को स्वीकार करने के लिए तैयार थे ताकि भूमि पर उगाए गए उत्पादों की प्रकृति की परवाह किए बिना इसके दायरे में 'बाद के संचालन' को शामिल किया जा सके। ये उत्पाद अनाज या सब्जियाँ या फल या बागान या विलासिता की वस्तुएँ या पहले से संकेतित वाणिज्यिक फसलें हो सकते हैं।

(28) उनके आधिपत्य ने तब इस सवाल पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या भूमि से संबंधित सभी गतिविधियों या पशुधन

के प्रजनन और पालन, डेयरी फार्मिंग, मक्खन सहित भूमि से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए 'कृषि' शब्द के आगे विस्तार के लिए कोई वारंट था। और पनीर बनाना, मुर्गीपालन, मुर्गीपालन आदि, जिसका विस्तार शब्द के शब्दकोश अर्थों और व्हार्टन के कानून लेक्सिकन में संकलित 'कृषि' की परिभाषाओं के साथ-साथ 1933 ए सी 618 में लॉर्ड कुलेन और लॉर्ड * राइट के उपदेश पर आधारित है। एचएल) 638 (जेड)। उनके आधिपत्य स्पष्ट रूप से 'कृषि' शब्द के पूर्वोक्त शब्दकोष अर्थ पर आधारित दृष्टिकोण से असहमत हैं और मूलजी सिका एंड कंपनी (11-ए) में डर्बीशायर, सी.जे. और के.ई. सुंदरा मुदलियार के मामले में विश्वरियाथा शास्त्री, जे. द्वारा इसकी सदस्यता ली गई है (सुप्रा) ने निम्नलिखित उत्तर दिया:—■

"हालाँकि, हमारी राय है कि केवल यह तथ्य कि किसी गतिविधि का भूमि से कुछ संबंध है या वह किसी तरह से भूमि पर निर्भर है, उसे इस शब्द के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है और 'कृषि' शब्द का ऐसा विस्तार अनुचित है।

इसे उन सभी गतिविधियों तक विस्तारित करने का कोई वारंट नहीं है जिनका भूमि से संबंध है या किसी भी तरह से भूमि से जुड़ा हुआ है। ऐसी गतिविधियों के संबंध में कृषि शब्द का उपयोग निश्चित रूप से शब्द का विरूपण होगा।

(29) तब उनके आधिपत्य ने देखा कि यह मूल विचार हर जगह मौजूद है कि इसके निचले भाग में भूमि की खेती

होनी चाहिए, भूमि की जुताई, बीज बोना, रोपण और भूमि पर किए गए इसी तरह के काम के अर्थ में। दूसरे शब्दों में, उनके आधिपत्य का मानना था कि इस प्रकार उगाई गई उपज को केवल कृषि उपज माना जाएगा।

(30) आयकर अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई 'कृषि आय' की परिभाषा और पहले से ही पुनरुत्पादित 'प्राथमिक भोजन' की परिभाषा की तुलना से पता चलेगा कि 'कृषि' या 'शब्द का सीमित विस्तारित अर्थ भी है। बिनॉय कुमार के मामले (सुप्रा) में भगवती, जे. द्वारा अपनाए गए 'कृषि उत्पाद' को इस मामले में स्वीकार्यता की गारंटी नहीं दी जाएगी, उक्त शब्द के व्यापक अर्थ को स्वीकार करना तो दूर की बात है, ताकि अभिव्यक्ति के साथ डेयरी, पोल्ट्री आदि को भी शामिल किया जा सके। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, 'कृषि उपज' जिसका विस्तार भगवती, जे. ने किया था, उस पर नाराज़ थीं।

(31) जब कृषि के व्यापक आयाम पर विचार किया जाता है तो यह माना जाता है कि इसमें बागवानी, वानिकी, डेयरी खेती आदि शामिल हैं। यह माना जाना चाहिए कि विधानमंडल को पता था कि अभिव्यक्ति 'कृषि' का संकीर्ण और व्यापक अर्थ है। यदि विधायिका का इरादा 'कृषि' शब्द का व्यापक अर्थ में उपयोग करने का था तो 'बागवानी' शब्द का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था क्योंकि कृषि के व्यापक अर्थ में बागवानी भी शामिल थी। इसलिए, वहाँ है. इस

निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि विधानमंडल द्वारा 'कृषि उपज' शब्द का उपयोग बागवानी की उपज के विपरीत मानव उपभोग के लिए भूमि पर खेती की जाने वाली वनस्पति साम्राज्य की प्राकृतिक उपज के संदर्भ में एक संकीर्ण अर्थ में किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भूमि पर पाले गए या भूमि की उपज पर पले जाने वाले पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम के कीड़ों को 'कृषि उपज' का हिस्सा बनाने का सवाल ही नहीं उठता। उपरोक्त से प्राप्त आगे की उपज के संबंध में ऐसा मामला अधिक स्पष्ट रूप से होगा। अतः 'दूध' को प्राथमिक भोजन नहीं माना जा सकता।

(32) अब दूसरे प्रस्ताव पर आते हुए यह देखा जा सकता है कि विश्लेषण के प्रयोजन के लिए खाद्य निरीक्षक को मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बिक्री माना जाता है और यदि विश्लेषण पर बेचा गया खाद्य पदार्थ है। मिलावटी पाया गया तो अपराध पूरा हो गया* और अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि खाद्य निरीक्षक को ठोस खाद्य पदार्थ विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए भेजा गया था। इस संबंध में खाद्य निरीक्षक, सिलिकट बनाम सी. गोपालन (12) में उनके आधिपत्य के निम्नलिखित अवलोकन को उपयोगी रूप से देखा जा सकता है: -

“संक्षेप में कहें तो हम AIR 1964- AH 199 और AIR 1965 Mad के निर्णयों से सहमत हैं। 98 इस हद तक कि वे इस सिद्धांत को निर्धारित करते हैं कि जब अधिनियम के तहत खाद्य निरीक्षक को किसी खाद्य पदार्थ की बिक्री होती है, जो मिलावटी पाया जाता है, तो आरोपी धारा 16 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होगा। (1) (ए) (i) अधिनियम की धारा 7 के साथ पढ़ें। हम इस बात से भी सहमत हैं कि खाद्य निरीक्षक द्वारा खरीदे गए खाद्य पदार्थ को बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यह भी मानना है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा जिस व्यक्ति से खाद्य सामग्री खरीदी गई है, उसे उस वस्तु का डीलर होना आवश्यक नहीं है। हम विपरीत प्रस्ताव रखने वाले निर्णयों से सहमत होने के इच्छुक नहीं हैं।

(33) उनके आधिपत्य के समक्ष मामले के तथ्य यह थे कि खाद्य निरीक्षक द्वारा एक चाय की दुकान से चीनी का एक नमूना लिया गया था और नमूना मिलावटी पाए जाने पर पति और पत्नी, जो क्रमशः प्रबंधक और मालिक थे, पर मुकदमा चलाया गया था। जिला-मजिस्ट्रेट, जिन्होंने पहली बार मामले को निपटाया, हालांकि यह तथ्य पाया गया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा खरीदा गया नमूना मिलावटी था, लेकिन उन्होंने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया कि आरोपी ने अपराध किया था, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी चाय की दुकान पर चीनी बेच रहे थे, जो उस मामले में तथ्य नहीं था। आरोपी जो बेच रहे थे वह चाय

थी और चीनी चाय के लिए रखी हुई थी जिसे ग्राहकों को बेचा जाता था और यह चीनी आरोपी की चाय की दुकान पर नहीं बेची जाती थी। केरल उच्च न्यायालय ने एक अपील पर आरोपियों को उसी आधार पर बरी कर दिया, जिस आधार पर उन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील पर, उनके आधिपत्य ने उच्च न्यायालय और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को उलट दिया।

(34) उनके आधिपत्य के समक्ष मामले के तथ्य यह थे कि खाद्य निरीक्षक द्वारा एक चाय की दुकान से चीनी का एक नमूना लिया गया था और नमूना मिलावटी पाए जाने पर पति और पत्नी, जो क्रमशः प्रबंधक और मालिक थे, पर मुकदमा चलाया गया था। जिला-मजिस्ट्रेट, जिन्होंने पहली बार मामले को निपटाया, हालांकि यह तथ्य पाया गया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा खरीदा गया नमूना मिलावटी था, लेकिन उन्होंने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया कि आरोपी ने अपराध किया था, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी चाय की दुकान पर चीनी बेच रहे थे, जो उस मामले में तथ्य नहीं था। आरोपी जो बेच रहे थे वह चाय थी और चीनी चाय के लिए रखी हुई थी जिसे ग्राहकों को बेचा जाता था और यह चीनी आरोपी की चाय की दुकान पर नहीं बेची जाती थी। केरल उच्च न्यायालय ने एक अपील पर आरोपियों को उसी आधार पर बरी कर दिया जिस आधार पर उन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किया गया था। सर्वोच्च

न्यायालय में एक अपील पर, उनके आधिपत्य ने उच्च न्यायालय और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को पलट दिया, आधिपत्य ने अधिनियम की धारा 7 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'स्टोर' को 'बिक्री के लिए भंडारण' के रूप में माना और आगे कहा कि भंडारण बिक्री के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थ धारा 16(1)(ए) के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

(35) मेरी राय में, लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) का अनुपात किसी भी तरह से सी. गोपालन के मामले (सुप्रा) के निर्णय के अनुपात से कम नहीं होगा क्योंकि मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री स्वयं अपराध है। मिलावटी खाद्य पदार्थ का भंडारण। किसी भी मामले में, लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) में 'स्टोर' शब्द पर उनके आधिपत्य द्वारा किया गया निर्माण स्टोर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के डीलर या धारक के लिए कम से कम मदद करता है यदि उस खाद्य पदार्थ का उपयोग करने का इरादा था भोजन की एक अन्य वस्तु के निर्माण के लिए जिसे बेचने का इरादा था जैसा कि वर्तमान में निम्नलिखित पैराग्राफ में देखा जाएगा।

(36) लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) में खाद्य निरीक्षक द्वारा मेसर्स एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड से आइसक्रीम, दूध, दही और मक्खन के नमूने विश्लेषण के लिए लिए गए थे। अभियुक्त की ओर से बचाव

में कहा गया था कि बेची गई खाद्य सामग्री जो संग्रहीत थे वे बिक्री के लिए नहीं थे। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि विचाराधीन खाद्य पदार्थों का उपयोग भोजन के अन्य सामान तैयार करने के लिए किया गया था जो ग्राहकों को परोसा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि एक होटल में एक निवासी ग्राहक को सभी सेवाओं और सुविधाओं के लिए समेकित शुल्क के बदले में एक होटल व्यवसायी द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन खाद्य पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों की बिक्री के बराबर नहीं है। मिलावट अधिनियम. उनके आधिपत्य ने उक्त निर्णय को उलट दिया और माना कि किसी होटल व्यवसायी द्वारा किसी ग्राहक को भोजन की आपूर्ति या पेशकश, जब आवासीय आवास और भोजन सहित अन्य सुविधाओं के लिए समेकित शुल्क लिया जाता है, तो भोजन के एक लेख की 'बिक्री' के बराबर है। उक्त अधिनियम. जब लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य के फैसले के आलोक में निर्णय लिया गया कि बिक्री की मात्रा क्या है, तो इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि एक चाय विक्रेता द्वारा चाय की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को स्टोर में रखा गया था। अपने ग्राहकों को परोसी जाने वाली सामग्री को बिक्री के उद्देश्य से संग्रहित किया गया माना जाएगा।

(37) अब हम उन निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) के अनुपात का पालन किया गया है।

(38) हरियाणा राज्य बनाम रमेश (14) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) के अनुपात का पालन करते हुए कहा कि जहां एक व्यक्ति ने अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए एक विशेष वस्तु का भंडारण नहीं किया था, जो उसने नहीं किया था। स्वेच्छा से बेचने पर, खाद्य निरीक्षक को यह आग्रह करने का अधिकार नहीं होगा कि उक्त व्यक्ति अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस वस्तु का एक हिस्सा उसे न बेचे। यदि ऐसी कोई वस्तु अवमानक पाई जाती है, तो भी अधिनियम के दंडात्मक परिणाम उस पर लागू नहीं होंगे।

(39) इस मामले में खाद्य निरीक्षक द्वारा एक हलवाई से खरीदी गई खांडसारी चीनी का एक नमूना लिया गया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि आरोपी चीनी की बिक्री का व्यवसाय नहीं कर रहा था, इसलिए खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई चीनी की खरीद अधिनियम की धारा 2 (xiii) में उल्लिखित 'बिक्री' की परिभाषा में नहीं आती है। राज्य द्वारा उस फैसले के खिलाफ की गई अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने ऐसा तब भी किया, जब मंगल दास 'v. इसके विपरीत रुख अपनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य (15) का हवाला दिया गया था।

(40) महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बनाम शंकर विलास, हिंदू होटल (16) के शंकर ने लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) के अनुपात को उसी तरह समझा, जैसा कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पहले ही नोट किया था। विद्वान न्यायाधीश ने महसूस किया कि लक्ष्मी नारायण टंडन का मामला (सुप्रा), जिसका निर्णय तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा किया गया था, भारत संघ बनाम के. फूड इंस्पेक्टर, कैल्डटुट बनाम चेरुकाटिल गोपालन, (18) में रिपोर्ट की गई जिसमें उनके आधिपत्य ने विशेष रूप से देखा था कि अधिनियम के दायरे में आने के लिए किसी व्यक्ति का विशेष रूप से डीलर होना आवश्यक नहीं है।

(41) इस मामले में एक रेस्टोरेंट से दूध का सैंपल लिया गया. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि दूध बिक्री के लिए नहीं था, बल्कि केवल चाय में इस्तेमाल होने के लिए था जिसे वह बेच रहा था। राज्य द्वारा उक्त बरी किए जाने के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

(42) हरियाणा राज्य बनाम ओम प्रकाश (19) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ रमेश के मामले (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण पर कायम रही।

(43) इस मामले में एक चाय विक्रेता से दूध का नमूना लिया गया. अभियुक्त का बचाव यह था कि वह दूध नहीं बेच रहा था, बल्कि दूध का जवास अपने ग्राहकों को परोसने के लिए चाय तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

(44) इस न्यायालय के दो और डिवीजन बेंच के फैसले, अर्थात् पंजाब राज्य बनाम रमेश कुमार, (20) और हरियाणा राज्य बनाम सेवा राम (21) ने भी एक-एक पैराग्राफ के संक्षिप्त निर्णयों में भी उसी का समर्थन किया है। देखना।
(45) म्युनिसिपल कमेटी, अमृतसर बनाम लछमन दास, (22) में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने, मंगल दास के मामले (सुप्रा) के अनुपात के बाद लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) पर ध्यान दिए बिना यह माना कि किसी भी वस्तु की बिक्री विश्लेषण के लिए भोजन की बिक्री के बराबर है और यह साबित करना जरूरी नहीं है कि आरोपी ने भोजन का वह सामान दूसरों को भी बेचा है और इसलिए, आरोपी प्रतिवादी द्वारा दलील दी गई कि 'उसने दूध नहीं बेचा लेकिन चाय बेची जिसका खर्च वहन नहीं कर सकता यह आगे माना गया कि यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने खाद्य निरीक्षक को दूध बेचा था जिसने दूध की खरीद के उद्देश्य को सूचित किया था।

(46) मेरी राय में, लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) का अनुपात उस दृष्टिकोण की गारंटी नहीं देता है जो इस न्यायालय ने रमेश के मामले (सुप्रा) में और बॉम्बे हाई कोर्ट

ने शंकर विलास, हिंदू होटल के मामले (सुप्रा) में लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन विद्वान न्यायाधीशों ने उन मामलों का फैसला किया, उन्होंने केवल उस फैसले के अनुपात पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जहां तक यह अभिव्यक्ति 'भंडार' के अर्थ से संबंधित था और उनके आधिपत्य द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया। 'बिक्री' शब्द का अर्थ. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उस मामले में उनका आधिपत्य यह था कि उस मामले में जिन खाद्य वस्तुओं का नमूना लिया गया था, उनका उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं की तैयारी में किया जाना था, जिन्हें बेचने का इरादा था और इसलिए, उक्त वस्तुएं स्टोर में रखे गए भोजन की मात्रा फैसले के पहले भाग में उनके आधिपत्य द्वारा दी गई अभिव्यक्ति 'स्टोर' की परिभाषा को पूरा करती है। उनके आधिपत्य ने दोषमुक्ति को रद्द कर दिया और मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया। इसलिए, मेरा विचार है कि रमेश का मामला (सुप्रा), ओम प्रकाश का मामला (सुप्रा), रमेश कुमार का मामला (सुप्रा), सेवा राम का मामला (सुप्रा) और शंकर विलास हिंदू होटल का मामला (सुप्रा), सम्मान के साथ, सही कानून का निर्धारण न करें, और इसलिए, शंकर विलास हिंदू होटल के मामले (सुप्रा) के शंकर से अपेक्षा करते हुए ये निर्णय; इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और किसी भी मामले में इन निर्णयों और 'स्टोर' शब्द के अर्थ के संबंध में लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचार का कोई फायदा नहीं होगा

जैसा कि वर्तमान में उत्पन्न होने वाले मामलों में 1 अप्रैल, 1976 के बाद दिखाया जाएगा।

(47) ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य द्वारा धारा 7 में प्रयुक्त 'स्टोर' शब्द पर किया गया निर्माण विधायी इरादे के विपरीत था और यही कारण था कि संशोधन अधिनियम द्वारा विधानमंडल ने न केवल इसे जोड़ा। धारा 7 के स्पष्टीकरण के बाद, लेकिन धारा 10 की उपधारा (2) में "बिक्री के लिए किसी अन्य खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए संग्रहीत या संग्रहीत" भी जोड़ा गया, जो खाद्य निरीक्षक की नमूना लेने की शक्तियों को संदर्भित करता है:

"स्पष्टीकरण: - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को किसी भी मिलावटी भोजन या गलत ब्रांड वाले भोजन या खंड में निर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ का भंडारण करने वाला माना जाएगा।
(iii) या खंड (iv) या खंड (v) यदि वह बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ के किसी भी लेख के निर्माण के लिए ऐसे भोजन का भंडारण करता है।

(48) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्मी नारायण टंडन के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य द्वारा धारा 7 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'स्टोर' पर लगाए गए निर्माण की 1 अप्रैल, 1976 के बाद उत्पन्न होने वाले मामलों से कोई प्रासंगिकता

नहीं होगी, जिस तारीख से, अन्य बातों के साथ, धारा 7 और 10 का उपरोक्त संशोधन प्रभावी हो गया था।

(49) अब तीसरे प्रस्ताव पर आते हुए, यह देखा जा सकता है कि मंगलदास के मामले में मामला उनके आधिपत्य द्वारा आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है (सुप्रा) और इस संबंध में उनके आधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-■

"श्री गनात्रा ने तब तर्क दिया कि रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा नहीं है। हमने स्वयं रिपोर्ट देखी है और इस तथ्य के अलावा कि जब इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया गया तो किसी भी अपीलकर्ता ने इसे अपर्याप्त बताकर चुनौती नहीं दी, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इसमें इस निष्कर्ष के समर्थन में आवश्यक डेटा शामिल है कि नमूना उनके द्वारा जांचे गए हल्दी पाउडर में मिलावट पाई गई। रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण और परीक्षणों के परिणाम निर्धारित करती है। तीन में से दो परीक्षणों और सूक्ष्म परीक्षण से हल्दी पाउडर में मिलावट का पता चला। सूक्ष्म परीक्षण से पराग डंठलों की उपस्थिति का पता चला। इसे तथ्यों से निपटने वाले न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के दिमाग को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

(50) उनके आधिपत्य के पास फिर से ध्यान सिंह बनाम सहारनपुर नगर पालिका (23) में इस तरह के विवाद की जांच करने का अवसर था और वे फिर से मंगलदास के मामले (सुप्रा) में व्यक्त किए गए पहले के दृष्टिकोण पर अड़े रहे। उनके आधिपत्य ने देखा कि इस विषय पर कानून का सही दृष्टिकोण कानपुर के नगर महापालिका बनाम श्री राम, (24) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है, जिसमें यह देखा गया है: -

"खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 13 के तहत सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट में विश्लेषण का तरीका या विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है और न ही परीक्षण लागू किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें विश्लेषण का परिणाम अर्थात् डेटा शामिल होना चाहिए जिससे यह अनुमान लगाया जा सके अधिनियम की धारा 2(1) में परिभाषित अनुसार खाद्य पदार्थ मिलावटी था या नहीं।

(51) इसलिए मेरे विचार में एक रिपोर्ट जिसमें विभिन्न घटकों का माप दिया गया है और फिर उल्लेख किया गया है कि ऐसे घटक निर्धारित मानक से नीचे हैं या कानून द्वारा निर्धारित अनुपात में मौजूद नहीं हैं और आगे विश्लेषक की राय का उल्लेख है कि विश्लेषण किया गया नमूना मिलावटी था, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अपर्याप्त डेटा वाली एक रिपोर्ट होना। ऐसी रिपोर्ट में न केवल वे निष्कर्ष शामिल होते हैं जिनसे यह राय बनेगी कि

नमूना मिलावटी है, बल्कि वह डेटा भी शामिल है जिस पर ऐसा निष्कर्ष आधारित है।

(52) चौथे और अंतिम प्रस्ताव से निपटने के लिए, सबसे पहले धारा 16-ए के वैधानिक प्रावधान पर ध्यान देना आवश्यक होगा जो निम्नलिखित शर्तों में है: -

"16-ए. मामले की संक्षिप्त सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी भी बात के बावजूद, धारा 16 की उपधारा (1) के तहत सभी अपराधों की सुनवाई प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त तरीके से की जाएगी। राज्य सरकार या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त वर्ग और धारा 262 से 265 के प्रावधान (उक्त संहिता के दोनों प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे मुकदमे पर लागू होंगे: - बशर्ते कि इस धारा के तहत संक्षिप्त मुकदमे में किसी भी दोषसिद्धि के मामले में, मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अधिक नहीं की 7 अवधि के कारावास की सजा पारित करना वैध होगा। बशर्ते कि जब इस धारा के तहत संक्षिप्त सुनवाई शुरू होती है, या उसके दौरान, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है यह पारित करते हुए कि किसी भी अन्य कारण से, मामले की संक्षिप्त सुनवाई करना अवांछनीय है, मजिस्ट्रेट, पक्षों को सुनने के बाद, उस आशय का एक आदेश दर्ज करेगा और उसके बाद किसी भी गवाह को वापस बुलाएगा, जिसकी जांच की गई

हो और सुनवाई या सुनवाई के लिए आगे बढ़े। उक्त संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामला।

(53) एकमात्र निर्णय, जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसने धारा 16ए के प्रावधानों की जांच की है, टी. बरई बनाम हेनरी एब हो और अन्य (25) में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यह एक ऐसा मामला था जिसमें प्रश्न यह था कि सवाल यह उठा कि क्या आरोपी पर खाद्य, औषधि और प्रसाधन सामग्री में मिलावट की रोकथाम (डब्ल्यू.बी. संशोधन) द्वारा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 16(1) (ए) के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।) 1973 का अधिनियम, या धारा 16ए के प्रावधानों के मद्देनजर उस पर संक्षेप में मुकदमा चलाया जाना था, जिसे संसद द्वारा 1976 के अधिनियम 34 में संशोधन करके 1 अप्रैल, 1976 से खाद्य अधिनियम में पेश किया गया था। धारा 16ए के प्रावधान 16 अगस्त, 1975 को उस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शुरू होने के बाद यह सक्रिय हो गया। संशोधन अधिनियम में, अन्य बातों के अलावा, धारा 16 (1) (ए) के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा के रूप में तीन साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया था। और उस मामले में विचार के लिए अगला प्रश्न यह था कि क्या उक्त संशोधन धारा 16(1)(ए) के पश्चिम बंगाली संशोधन द्वारा प्रदान की गई आजीवन कारावास की अधिकतम सजा को कम करने

का प्रभाव रखता है और यदि ऐसा है तो फिर क्या लंबित कार्यवाही धारा 16ए के तहत प्रक्रिया द्वारा शासित होगी।

(54) उनके आधिपत्य ने माना कि संशोधन अधिनियम 34 ने 1 अप्रैल, 1976 से पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम को निहित रूप से निरस्त कर दिया था।

(55) उस मामले में ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि वह मामले की सुनवाई करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने बी. मन्ना बनाम डब्ल्यू.बी. राज्य (26) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले के मद्देनजर आपत्ति बरकरार रखी। मामले को डिवीजन बेंच में ले जाया गया, जिसने बी. मन्ना के मामले (सुप्रा) में फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि 1 अप्रैल, 1976 से केंद्रीय संशोधन लागू होने के बाद, धारा 16 के तहत दंडनीय अपराधों के मुकदमे की सभी कार्यवाही लंबित हैं। 1)(ए) जैसा कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जो समाप्त नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम द्वारा शासित होना बंद हो जाएगा और केंद्रीय संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम के दायरे में आ जाएगा और इसलिए, ऐसे अपराध यद्यपि इस तरह के संशोधन से पहले किए गए अपराध केंद्रीय संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 16-ए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के

अनुसार परीक्षण योग्य थे। पीठ ने तदनुसार त्रय मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और उसे मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

(56) फैसले में धारा 16-ए के प्रावधान के अनिवार्य या निर्देशिका चरित्र के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जहां तक सज़ा की मात्रा का सवाल है, उनके आधिपत्य मुख्य रूप से यह निर्धारित करने में चिंतित थे कि क्या केंद्रीय संशोधन ने पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम को निरस्त कर दिया है।

(57) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा 16-ए के निर्माण का प्रश्न व्यापक है और पहले सिद्धांतों पर प्रयास करना होगा। मेरे विचार में, विधायिका ने मुख्य रूप से न्यायालयों को अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने में सक्षम बनाने के लिए सारांश परीक्षण की शुरुआत की। केवल एक त्वरित प्रतिशोध ही संभावित अपराधियों को दिए गए अपराध को करने से रोकने के उद्देश्य को पूरा कर सकता है, जो न केवल चरित्र में अत्यधिक असामाजिक था, बल्कि खतरनाक अनुपात ग्रहण करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता था, - चूंकि सारांश परीक्षण स्वाभाविक रूप से कम निष्पक्ष होता है नियमित सुनवाई की तुलना में विधायिका उन अपराधियों को एक लाभ प्रदान करने के लिए आगे बढ़ी, जिन पर संक्षेप में मुकदमा चलाया जाता है कि उनके मामले में सजा की

अधिकतम खुराक एक वर्ष के कठोर कारावास से अधिक नहीं बढ़ेगी, लेकिन यदि अपराध ऐसा था कि इसके लिए सजा की मात्रा से अधिक की आवश्यकता होगी। सारांश परीक्षण के परिणामस्वरूप सम्मानित किया जा सकता है, विधानमंडल ने मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में ऐसा कहने के लिए अधिकृत किया और फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ा।

(58) उपरोक्त से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधानमंडल का इरादा है कि अधिनियम की धारा 16(1) के तहत सभी अपराधों की सुनवाई विशेष रूप से अधिकृत मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाए, जब तक कि ऐसा मजिस्ट्रेट लिखित रूप में यह न कहे कि अभियुक्त अधिक सजा का हकदार है और इसलिए उस पर दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाया जाए। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त सुनवाई तभी कर सकते हैं जब वे विशेष रूप से इतने सशक्त हों। इसलिए, जब तक वे विशेष रूप से इतने सशक्त नहीं होंगे, उनके सारांश त्रिदल धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। हालाँकि, एक बार जब न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष रूप से इतने सशक्त हो जाते हैं, तो वे एक मामले और दूसरे मामले के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं और - उन्हें धारा 16(1) के तहत हर अपराध की सुनवाई पहली बार में सारांश तरीके से करनी होगी और यदि कोई अपराध है। जैसे कि अपराधी को सारांश परीक्षण के परिणामस्वरूप

दी जा सकने वाली सजा से अधिक सजा देने की आवश्यकता होती है, तो उस मामले में लिखित रूप में ऐसा आदेश पारित करने के बाद, वह ऐसे अपराधियों पर संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाने का हकदार होगा। दिया गया अपराध।

(59) स्पष्टता के लिए, निर्णय की शुरुआत में निर्धारित प्रस्तावों के लिए प्रस्तावित उत्तर को गिनाना वांछनीय होगा। हमारा मानना है कि:-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 2(xiia) के अंतर्गत दूध प्राथमिक भोजन नहीं है।

(2) अधिनियम की धारा 10 के अनुसार खाद्य निरीक्षक द्वारा चाय विक्रेता द्वारा रखे गए दूध या चीनी या चाय के नमूने की खरीद बिक्री के लिए नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को परोसने के लिए चाय तैयार करने में उपयोग करने के लिए की जाती है। अधिनियम की धारा 2(xiii) के साथ पठित धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार बिक्री के बराबर है।

(3) सार्वजनिक विश्लेषक की एक रिपोर्ट को कानून में स्वीकार्य माना जाता है, ऐसी रिपोर्ट में सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षणों के तरीके और तरीके के बारे में जानकारी शामिल नहीं होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नमूना मिलावटी था या नहीं नहीं। यदि वह रिपोर्ट में अपने द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों को इंगित करता है तो यह पर्याप्त है।

(4) अधिनियम की धारा 16(1) के तहत अपराधों का सारांश परीक्षण करना तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त नहीं किया जाता है।

एक बार जब वे इतने सशक्त हो जाते हैं, तो धारा 16(1) के तहत हर मामले को पहली बार में अनिवार्य रूप से सारांशित तरीके से आजमाया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट ने उक्त प्रावधान में उल्लिखित कारणों पर विचार नहीं किया हो, अपराधी पर मुकदमा चलाना आवश्यक है हमारे दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से।

(60) उक्त उत्तरों के साथ हम इन तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को इस फैसले में निर्धारित कानून के आलोक में योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए भेजते हैं।

प्रेम चंद जैन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, -मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा

और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा